International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
May-June 2017, Volume-4, Issue-3
P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org
Email- editor@ijesrr.org

भारत में विकास जनित समस्याएँ एवं उनका निदान

Dr. Suman Gupta

Lecturer in Sociology

Govt College Kaladera ,Jaipur

सार

किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए उस देश की अर्थव्यवस्था के स्वरूप गुण व दोषों को समझना अति आवश्यक होता है ताकि उसकी कमियों व कठिनाइयों को दूर करके उसमें आवश्यक सुधार किए जा सकें जिसके आर्थिक विकास की गतिशीलता में वृद्धि की जा सके। समाजशास्त्र मानव समाज को निर्मित करने वाली इकाईयों एवं इसे बनाए रखने वाली संरचनाओ तथा संस्थाओं का अध्ययन अनेक रूपों से करता है समाजशास्त्रियों एवं सामाजिक विचारकों ने अपनी रूचि के अनुसार समाज के स्वरूपों संरचनाओ संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन किया है। समस्या विहीन समाज की कल्पना करना असम्भव सा प्रतीत होता है।

वर्तमान समय में भारतीय समाज अनेक सामाजिक समस्याओं से पीड़ित है जिनके निराकरण के लिए राज्य एवं समाज द्वारा मिलकर प्रयास किये जा रहे हैं। भारतीय समाज की प्रमुख समस्याओं में जनसंख्या विस्फोट, निर्धनता, बेरोजगारी, असमानता, अशिक्षा, गरीबी, आतंकवाद, घुसपैठ, बाल श्रमिक, श्रमिक असंतोष, छात्र असंतोष, भ्रष्टाचार, नशाखोरी, जानलेवा बीमारियां, दहेज प्रथा, बाल विवाह, बालिका भ्रूण हत्या, विवाह विच्छेद की समस्या, बाल अपराध, मद्यपान, जातिवाद, अस्पृश्यता की समस्या ये सभी समाजिक समस्याओं के अन्तर्गत आती है।

परिचय

प्रगति तथा विकास के आर्थिक सन्दर्भ में एक बात और महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास के संदर्भ में प्रगति तथा विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहां तक कि एक के बिना दूसरे का औचित्य सिद्ध नहीं किया जाता सकता है। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है। कोई भी वृद्धि अपने मे महत्वपूर्ण नहीं है, जब तक कि इसके साथ ढांचागत परिवर्तन न हो ।प्रगति के बिना विकास और विकास के बिना प्रगति का औचित्य प्रकट करना कठिन है। दोनो एक दूसरे के पूरक हैं। किसी देश का आर्थिक विकास तभी सम्भव है जब सभी क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाई जावे तथा जीवन स्तर में अनुकूल सुधार हो । किसी देश की आर्थिक प्रगति बाजार की अपूर्णता तथा विदेशी बाजार के प्रभाव को बिना कम किये सम्भव नहीं हो पाती। आर्थिक विकास की सम्भावनाऐं न केवल आर्थिक साधनों पर प्रकाश डालती है, वरन देश को प्रतिकूल अवस्थाओं से भी मुक्त करने का बोध कराती है। वे प्रतिकूल अवस्थाऐं रूढ़िवादी प्रवृत्तियों के प्रचलन एवं उपभोग में वृद्धि न होने से उत्पन्न हो जाती है। आर्थिक विकास विभिन्न तत्वों के प्रभाव से विभिन्न गति से होता है और इसका प्रभाव दीर्घकालीन होता है। यदि किसी समय कुछ

अस्थायी कारणों से आर्थिक सुधार हो जाये तो हम उसे आर्थिक विकास नहीं कह सकते। वह केवल आर्थिक विकास में सहायक हो सकता है। आर्थिक विकास की गति अल्पकालीन परिवर्तनों से नहीं आँकी जा सकती। काफी समय तक बहुमुखी आर्थिक प्रगति होने पर ही विकास पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव देश की राष्ट्रीय आय पर स्थायी वन जाते हैं। इनके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। उत्पादन बढ़ने लगता है और मूल्य स्तर पर पूंजी संचय नवीन उत्पादन पद्धति अतिरिक्त साधन जनसंख्या का आकार तथा उपभोग प्रवृत्तियां संसाधन में वृद्धि करती हैं। अतः आर्थिक वृद्धि इन सभी साधनों द्वारा मनुष्यों के उपयोग के लिये अतिरिक्त उत्पादन व सेवाओं से होती है। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि इन साधनों के प्रयोग और समन्वय से निरन्तर वृद्धि होती ही रहे और कुल वास्तविक आय बढ़ती जाये । परिस्थितियों में परिवर्ततन होने से आर्थिक प्रगति अधोगामी भी हो सकती है। जब आय वृद्धि की अपेक्षा जनसंख्या बढ़ने से उपभोग में अधिक वृद्धि हो जाये व जनसंख्या की वृद्धि अथवा उपभोग में वृद्धि आय की वृद्धि के बराबर हो जाने पर यह वृद्धि स्थिर भी हो जाती है। आर्थिक विकास में ये सभी अवस्थाऐं आती हैं, परन्तु उनका कुल दीर्घकालीन प्रभाव धनात्मक ही होता है।

आर्थिक विकास के मापदण्ड के बारे में अर्थशास्त्रियों के अलग अलग मत है। कुछ अर्थशास्त्री देश की अर्थव्यवस्था में हुए औद्योगीकरण की गति को ही आर्थिक विकास का सूचक मानते हैं। उनके अनुसार औद्योगीकरण द्वारा वस्तुओं का निर्माण अधिक होता है जिससे पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है। कुछ विद्वान उन्नति के साधनों की उत्पादकता में हुई वृद्धि को आर्थिक विकास मानते हैं। उनके अनुसार आर्थिक विकास की गति कुल उत्पादन के साधनों का समन्वय है। अर्थात $F = O / KxLxQ\ 1$ । इस समीकरण में विकास गति उत्पादन की मात्रा देश के प्राकृतिक साधन कुल श्रम शक्ति और उद्यमी का योगदान है। परन्तु यह तभी सम्भव है जब देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति निर्मित रहे। किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि उस देश में हुए पूंजी निर्माण की गति तथा पूंजी का उत्पादन से प्रति इकाई अनुपात द्वारा ज्ञात हो जाती है। प्रत्येक देश चाहता है कि उसमें रहने वालों की आय अधिक हो और उनके जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सके। आधुनिक राज्यों के कल्याणकारी उद्देश्यों के अनुरूप प्रत्येक देश अपने नागरिकों को आर्थिक उत्पादन और उपभोग में समान अवसर देना चाहता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार देश की आर्थिक क्रियाओं में अधिक से अधिक योगदान देकर उसे समृद्धिशाली बना सके। देश की आर्थिक प्रगति के लिये यह आवश्यक है कि सामान्य जनता में आर्थिक उन्नति करने की भावना प्रबल हो और वे अपनी लगन से आय की मात्रा बढ़ाने में निरन्तर प्रयत्न करते रहे। मानव की स्थिति और नियति के बारे में आजकल जो बहस हो रही है, उसमें आधुनिकीकरण और विकास दो बीज शब्द बन गये हैं। विभिन्न बौद्धिक इतिहास होने पर भी लक्ष्यों को पुर्नपरिभाषित करने और वैचारिक पृष्ठभूमि तथा अध्ययन विधि दोनो ही दृष्टियों से एक दूसरे से अधिक मेल खाने के कारण अब ये वास्तविक अर्थ में एक दूसरे से अधिक निकट भी आ गये हैं । दोनो की तीन सन्दर्भ बिन्दुओं में साझेदारी हैं। प्रथम ये समाज की स्थिति की ओर इंगित करते हैं । आधुनिकीकरण को मनाने वाले विचारक परम्परागत संक्रमण कालिक

तथा आधुनिकीकृत समाजों में भेद करते हैं। दूसरी ओर विकास की अवधारणा माननेवाले विचारक अविकसित विकासशील और विकसित समाजों की चर्चा करते हैं। दूसरे दोनो ही ऐसे लक्ष्यों को रेखांकित करते हैं जो आधुनिकीकरण या विकास के आदर्श कार्यक्रमों की एक रूपरेखा सामने रखते हैं। तीसरी दोनो ही अवधारणाऐं एक प्रक्रिया की ओर संकेत करती हैं।

विकास की प्रक्रिया को सही अर्थों में सहभागी बनाने वाले प्रयास के विषय में सोचना आवश्यक है। यह तभी सम्भव होगा जब आम आदमी की सही अर्थो में न कि नाम मात्र की सत्ता और संसाधनों तक पहुंच हों। वह प्रजातन्त्र जहां केवल समय समय पर चुनाव होते रहते हैं सही अर्थों में सहभागी प्रजातंत्र नहीं। लोगो के द्वारा पहल करने की इच्छा को खंडित नहीं करना चाहिए और जनजागरण का अर्थ अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिपादित सत्ता के केन्द्रों द्वारा लिये निर्णयों का आम जनता द्वारा पालन नहीं माना जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में लोगों की अपने बारे में वर्तमान और भविष्य के बारे में ही निर्णय लेने के अतिरिक्त विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भी प्रमुख भूमिका होनी चाहिए।

व्यापक स्तर पर विकास की प्रक्रिया पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलत नहीं रही है। इसका बड़ा घातक प्रभाव पड़ा है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि बहुत सी सभ्यताऐं इसलिए समाप्त हो गयी कि उन्होंने पर्यावरण का एक सीमा से अधिक दोहन किया । विलम्ब से ही सही पश्चिमी जगत ने इस समस्या को संवेदनशीलता के साथ हल करने में जागरूकता दिखाई है। तीसरी अधि -कांश विकासशील देशों में एक गलत धारणा यह फैली हुई है कि उद्योगीकरण की निम्न मात्रा के कारण वे पर्यावरण के प्रमुख खतरों से बचे हुए हैं। यह सच नहीं है। पर्यावरण की चेतना विकासशील देशों में भी बढ़ानी है जिससे कि वे अपने पर्यावरण के संरक्षण और अभिवृद्धि के लिए समय पर कदम उठा सके। पर्यावरणविदों की भयानक परिणमोवली चेतावनियों को मात्र एक फैशन नहीं मानना चाहिए।

विकास और नियोजन में एक बहुत बड़ी कमी इस प्रक्रिया को धारण करने की क्षमता का अभाव है। वे उसकी निरन्तरता को बनाए रख सकने में समर्थ नहीं है। अधिकांश विकास शील देश चेतन या अचेतन रूप से अपने संसाधनों और सीमाओं के बारे में बिना सोचे हुए पश्चिम का अनुकरण कर रहे हैं। यह सिद्ध है कि समृद्ध देश भी ऐसे बिन्दु पर पहुंच गये हैं जहां विकास, कम अर्थो में धारणयोग्य नहीं रह गया है, और उसके भयंकर त्रासद परिणाम हो रहे हैं। से कम कुछ मुद्रास्फीति बेरोजगारी मंदी तथा पर्यावरण के खतरे आदि इसके प्रभाव हैं।

उद्देश्य

- आर्थिक विकास की गतिशीलता एवं समस्याएँ
- भारतीय विकास अवधारणा रणनीति तथा प्रक्रिया

आर्थिक विकास के निर्धारक घटक

आर्थिक विकास के निर्धारक घटक गैर आर्थिक घटक और आर्थिक घटक में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है क्या गैर आर्थिक कारक आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं या आर्थिक विकास गैर आर्थिक कारकों से अधिक प्रभावित होता है। कुछ लोग गैर आर्थिक घटकों को अधिक महत्वपूर्ण बताते हैं। उनका तर्क होता है कि आर्थिक कारक तो प्रतिफल को प्रभावित करते हैं जबकि गैर आर्थिक कारक निर्णायक होते हैं। अतः सामाजिक मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक पहलू अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य केवल एक आर्थिक प्राणी नहीं है । आर्थिक पहलू उसके जीवन का एक पक्ष मात्र है और दूसरे पक्ष आर्थिक विकास के पहल करने में सहायक होने के साथ साथ कभी कभी विकास अवरुद्ध भी कर सकते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान दशा

आर्थिक संकेतकों से पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की अधिक तेजगति से विकास कर रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है हमारी अर्थव्यव्यवस्था का बचत तथा निवेश अनुपात काफी अधिक है पूंजी निर्गत अनुपात से स्पष्ट है कि हमारी उत्पादकता का स्तर भी सम्माननीय है। पूंजी प्रवाह के अपेक्षाकृत कम स्तर के बावजूद बाहरी क्षेत्र में हमारी स्थिति ठीक ठाक है। यह स्थिति इस बात का प्रमाण है कि विदेशी पूंजी निवेशकों की कम दिलचस्पी के बावजूद घरेलू निवेशकों का मिलाजुला दृष्टिकोण है। वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक के आधार पर तय हमारी स्थिति से उस विश्वास की झलक मिलती है जो कम अवधि में ही हमारे विकास की रफ्तार को देखकर व्यक्त किया गया है। अलबत्ता विकास प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक पर हमारी स्थिति से जो तसवीर उभरती है वह भविष्य में प्रति व्यक्ति आय में विकास को लेकर आशा जनक नहीं कही जा सकती। अन्य संकेतकों के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है कि मौजूदा विकास को गति देने वाले कारक भविष्य में विकास को देने वाले कारकों के मुकाबले कहीं अधिक मजबूत है।

श्रम प्रधान तकनीकी

विद्वानों के एक वर्ग का मानना है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां श्रम की बहुलता और पूंजी की कमी हो, वहां पर श्रम प्रधान तकनीकी को अपनाना अधिक उपयुक्त होगा। इन राष्ट्रों के लिए यह बुद्धिमानी नहीं होगी कि अपने सीमित साधनों के उपयोग के लिये विकसित राष्ट्रों की तकनीकी की नकल करें। यदि वे ऐसा करते हैं तो इसका तात्पर्य हुआ कि हम उत्पादन की ओर प्रदर्शन प्रभाव को चाहते हैं इसका सीधा आशय है कि वह राष्ट्र चलना जानने से पूर्व दौड़ने का प्रयत्न कर रहा है ।

बेरोजगारी और ग्राम्य विकास योजनाऐं

यह स्पष्ट है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में गांवों में और शिक्षित वर्ग की तुलना में अशिक्षित वर्ग में बेरोजगारी अधिक व्याप्त है। इस को बेरोजगारी दूर करने के लिए हमें निवेश का रूंख ग्रामीण क्षेत्रों और अधोसंरचना की ओर करना होगा। भारी निवेश की अपनी सीमाएं है और भारी निवेश रोजगार सृजन के अवसरों में तब तक फलदायी सिद्ध नहीं होगा जब तक कि मानवीय संसाधनों का विकास शिक्षण और प्रशिक्षण द्वारा नहीं किया जाता। यदि हम भारी निवेश द्वारा रोजगार सृजन की बात करते हैं तो यह एक पक्षीय विचार होगा और श्रमशक्ति की मांग और पूर्ति में व्यापक असन्तुलन पैदा करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों की बेरोजगारी को दूर करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार द्वारा अनेक प्रयत्न किये गये हैं। गरीबी और बेकारी एक दूसरे के पर्याय बन गये हैं अतः ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण इलाकों में समुचित विकास के लिए मुख्य तौर पर दो प्रकार के कार्यक्रम चला रहा है।

विकास कार्यक्रमों की जानकारी का अभाव

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का निर्धारण और क्रियान्वयन एक गम्भीर चिन्तन का विषय है। पंचायती राज की नवीन व्यवस्था से यह अपेक्षा की गई थी कि ग्राम पंचायतें अपने विकास सम्बन्धी कार्यक्रम स्वयं तैयार करेगी और उनका क्रियान्वयन भी स्वयं ही करेगी। यह व्यवस्था लागू करते समय यह मान लिया गया था कि जो प्रतिनिधि चुनकर आएंगे वे विकास से सम्बन्धित विषयों की पहचान करने तथा उससे सम्बन्धित कार्यक्रम बनाने में समर्थ होंगे। किन्तु आरक्षण के चलते बड़ी संख्या में कमजोर वर्गो के प्रधान उपप्रधान तथा पंचायत सदस्यों के पास गाँवो में संचालित विकास कार्यक्रमों तथा उनकी दक्षता गुणवत्ता और स्वाधिकारिता पूर्ण, निरन्तरता बढ़ाने उनकी कमियों और कमजोरियों को मिटाने तथा गांवो की उपेक्षित उत्पीड़ित और सीमान्त बहुसंख्यक जनशक्ति को इन प्रक्रियाओं में अग्रणी तथा प्रमुख भूमिका प्रदान करने के लिए नीतिगत व्यवस्था करना भारत में राष्ट्रीय सामाजिक समन्वित विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्राथमिक अंग है।भारतीय विकास अवधारणा रणनीति तथा प्रक्रिया की सार्थक प्रभावशील और अपरिहार्य कसौटी है ।

शिक्षा की कमी-

जहां शिक्षा का अभाव रहेगा वहां अज्ञान का अंधेरा छाया रहना स्वभाविक है। विकास और प्रगति की अनेक बातें कहीं और सुनी जाने के बावजूद राज्य में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की दशा अभी भी बद्तर है। मुख्य रूप से कमजोर वर्गो और महिलाओं की शिक्षा की दशा और भी शोचनीय है। पंचायतें ही अब शिक्षा समितियों के माध्यम से ग्रामीण शिक्षा की व्यवस्था तथा उससे सम्बन्धित कार्य देखेगी। पंचायतों के लिये चुने गये कमजोर वर्गो के प्रतिनिधि तथा महिलाएं गांव के सजग प्रतिनिधि के रूप में गांव में फैली घोर निरक्षरता की भयावहता को कम करने की दिशा में अपनी भूमिका निभाएंगे। किन्तु यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि इस वर्ग से चुनकर आए प्रतिनिधि स्वयं शिक्षित हों । सर्वेक्षणों से यह बात स्पष्ट है कि कमजोर वर्गो

तथा महिलाओं में शिक्षा का स्तर काफी निम्न है और उनमें पर्याप्त संख्या में निरक्षर भी है। वे ग्राम्य विकास के कार्यो से भली भांति परिचित भी नहीं है। ऐसी स्थिति में ये प्रतिनिधि विकास के कार्यो की योजना तैयार करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने में स्वभाविक रूप से समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। तथा उनकी अज्ञानता और अदूरदर्शिता के कारण पंचायतों के कार्यो का क्रियान्वयन स्थगित सा हो गया है। ये लोग ग्रामीण शिक्षा के विकास में अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं।

पंचायत स्तर पर बजट की जानकारी न होना-

संविधान के 73वें संशोधन में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने तथा इस बारे में राज्यपालों को सुझाव देने के लिए पंचवर्षीय अवधि वाले राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। आयोग को यह बताना था कि करों शुल्कों फीस और चुंगी आदि स्रोतो से जो आमदनी राज्यों को प्राप्त होती हैं उसे राज्य और ग्राम पंचायतों क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के बीच बंटवारे के नियम क्या होंगे। इसके अतिरिक्त आयोग को राज्यों की समेकित निधि में से विभिन्न स्तरों पर पंचायतों को सहायता अनुदान देने सम्बन्धी सुझाव समय समय पर देने थे। सरकार की अनेक घोषणाओं के बावजूद पंचायतों की वित्तीय स्थिति अभी सुदृढ़ नहीं हो पायी है। यह स्थिति शीघ्र समाप्त नहीं की गई तो कमजोर वर्गो का नेतृत्व प्रभावी नहीं हो पाएगा।

स्वायत्तता की कमी

शासन द्वारा पारित उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को 29 अधिकार ऐसी शर्तों के अधीन सौंपे गये हैं जिन पर सरकार का प्रत्यक्ष रूप से अधिकार होगा और समय समय पर विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन रहते हुये ग्राम पंचायतें उन कार्यो का सम्पादन करेगी। किन्तु जिन पंचायतों में कमजोर वर्गो के प्रधान और उपप्रधान कार्य कर रहे हैं उनके कार्यो के क्रियान्वयन में सरकार तथा गांव के प्रभावशाली लोगो का हस्तक्षेप वना रहता है इससे गांव के विकास सम्बन्धी कार्य सुगमतापूर्वक नहीं हो पाते। कमजोर वर्ग के पंचायत प्रतिनिधियों में इस दिशा में सरकार और गांव के प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा बढ़ते जा रहे हस्तक्षेप को लेकर असंतोष व्याप्त हैं जो विभिन्न स्तर पर होने वाली बैठकों में मुखर रूप से देखने को मिलता है।

गुणात्मक विकास की सोच में कमी

वास्तविक अर्थो में गांव के विकास का अर्थ गांव में रहने वालो के जीवन को सुखमय वनाने से है। जिसे प्राप्त करने के लिए एक ओर भौतिक संरचना से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार किया जाना आवश्यक है, वही दूसरी ओर इनका अनुकूलमत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इनके उपभोक्ता अर्थात ग्रामवासियों की जीवन शैली से जुड़े पक्षों में गुणात्मक सुधार के लिए भी प्रयास करना जरूरी हैं इसके लिये मानवीय संसाधनों के विकास को पंचायती राज संस्थाओं का प्रमुख दायित्व माना जाता है। विकास

को स्थायी गति प्रदान करने लिए इन दोनों में न्यायपूर्ण सन्तुलन स्थापित किया जाना आवश्यक है। इस सन्तुलन को साधने का कार्य सबसे अच्छे ढंग से पंचायते और प्रधान ही कर सकते हैं। इसीलिये इनसे जुड़े समस्त विषयों को ग्राम पंचायतों की सूची में सम्मिलित किया गया है। सूची में वर्णित विषयों पर कार्य करने का अधिकार न मिल पाना तो ग्राम पंचायतों और ग्राम प्रधानों को प्रतिकूलतः प्रभावित कर रहा है।

विकासशील देशों की प्रमुख समस्याओं के निवारण के उपाय

अन्धानुकरण रोकना

विकासशील देशों को विकसित देशों के अन्धानुकरण से बचना चाहिए। हमें अपने देश के अर्द्ध-विकसित साधनों ,सम्भावनाओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखकर परियोजनाएं तैयार करनी चाहिए

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तार

समाजवादी समाज की स्थापना के नाम पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना को हतोत्साहित किया जाना आवश्यक है। उद्योगों का चयन आर्थिक आधार पर होना चाहिए एवं महत्वपूर्ण पदों की नियुक्तियों में पक्षपात नहीं होना चाहिए। अकुशल प्रबन्धन एवं भ्रष्टाचार से मुक्ति का प्रयास भी आवश्यक है।

निश्चित कार्यक्रम

सरकार के पास एक निश्चित कार्यक्रम होना चाहिये। वितरण सहित सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग की प्राथमिकताओं को निश्चित कर देना चाहिये । सार्वजनिक क्षेत्र में साधनों का वितरण बुद्धिमत्तापूर्वक एवं उचित तरीके से होना चाहिए।

आत्मनिर्भरता

प्रत्येक देश में आत्म-निर्भरता की प्रवृत्ति को ठीक माना जाता है, किन्तु आत्मनिर्भरता न सम्भव है, न लाभप्रद । विकासशील देशों को आत्म-निर्भरता और अन्तर्राष्ट्रीयकरण के मध्य का मार्ग अपनाना चाहिए।

निजी क्षेत्र की उपेक्षा

विकासशील देशों में निजी क्षेत्रों की उपेक्षा की जाती है। दोषपूर्ण सरकारी नीतियों के कारण निजी क्षेत्र का आर्थिक विकास नहीं हो पाता। अत्यधिक संरक्षण एवं दोषपूर्ण लाइसेंस नीति से निजी क्षेत्र में अनार्थिक इकाइयों का विस्तार होता है। निजी क्षेत्र के लिए लाइसेन्स नीति विकास के अनुकूल होनी चाहिए।

अनार्थिक इकाइयाँ

विकासशील देशों में प्रायः अनार्थिक इकाइयों की स्थापना की जाती है जो देश के आर्थिक ढाँचे के अनुकूल नहीं होती। देश में ऐसे उद्योग स्थापित किये जाने चाहिए जिससे देश के लिए साधन जुटाए जा सकें।

तकनीकि चयन

देश की परिस्थितियों के अनुसार उद्योगों एवं अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कोटि की तकनीकि का प्रयोग होना चाहिए जिससे कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके।

जनसंख्या वृद्धि को रोकना

विकासशील देशों में अत्यधिक जनसंख्या ऊँची जन्म-दर एवं मृत्यु दर के कारण है। अतः स्वास्थ्य सुविधाओं एवं नियोजन के साधनों को बढ़ावा देकर जनसंख्या वृद्धि को रोकने का प्रयास करना चाहिए।

सामाजिक रूढ़ियों में बदलाव

विकासशील देशों में अनेक सामाजिक रूढ़ियाँ होती हैं। जन-चेतना के माध्यम तथा शिक्षा के प्रचार-प्रसार से उन सामाजिक रूढ़ियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

बेरोजगारी एवं निर्धनता

सरकार को रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराकर समाज में व्याप्त निर्धनता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उच्च, मध्य एवं निम्न वर्ग में बंटे समाज में आय के वितरण की असमानता को दूर करना चाहिए।

जन सहयोग

जनता को विश्वास दिलाना चाहिए कि उनके प्रयत्नों का प्रतिफल उन्हें ही प्राप्त होगा। जनता की अभिरुचि एवं परामर्श भी समय-समय पर लेना आवश्यक है । जनसहयोग प्राप्त करने के लिए योजना का निर्माण नीचे से नियोजन सिद्धान्त पर किया जाना चाहिए।

भ्रष्टाचार को मिटाना

योजनाओं का संचालन एवं क्रियान्वयन प्रशासन के हाथों होता है अतः योजनाओं के लाभों को जनसाधारण तक पहुँचाने के लिए भ्रष्ट प्रशासन को मिटाना आवश्यक है।

निष्कर्ष

दुनिया की आबादी का छठा हिस्सा होने के कारण भारत का आर्थिक विकास न केवल महत्वपूर्ण है इसके नागरिकों के लिए निहितार्थ लेकिन वैश्विक प्रभाव। जबकि इसके बारे में थोड़ा संदेह है अधिकांश अन्य बड़े विकासशील देशों की तुलना में **1990** के बाद पर्याप्त आर्थिक परिवर्तन भारत बाजार-आधारित सुधार के अधिकांश उपायों पर धीरे-धीरे आगे बढ़ा है निजीकरण, व्यापार, या वित्तीय क्षेत्र का उदारीकरण। बहरहाल, इस अवधि के दौरान इसकी वृद्धि हुई एशिया के बाहर विकासशील देशों के औसत से लगभग दोगुना और बहुत बेहतर रहा है अपने अतीत की तुलना में फिर भी जबकि सभी राजनीतिक दलों ने कमोबेश व्यापकता को स्वीकार कर लिया है बाजार- उन्मुख अर्थव्यवस्था में बदलाव का जोर (हालांकि विशिष्ट प्राथमिकताओं पर भिन्न यहां तक कि दो दशकों से अधिक समय के बाद सुधार का कोई प्रत्यक्ष राजनीतिक क्षेत्र नहीं है। यदि भारत हाल ही के वर्षों में हासिल की गई दर से आगे बढ़ता रहा, तो इसकी वैश्विक उपस्थिति बढ़ेगी।

संदर्भ

- https://www.answerduniya.com/2012/10/vikaasasheel-deshon-kee-samasyaen.html
- https://digicgvision.in/jansankhya-samasya-aur-samadhan/
- https://www.nios.ac.in/media/documents/331coursehindi/Module_4/Lesson_29.pdf
- http://gramodayachitrakoot.ac.in/wp-content/uploads/2012/07/Book-Issues-and-Problems-of-Development.pdf
- https://vidyadoot.com/bharat-ke-vikas-mein-pramukh-badhaen/
- https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/inconsistent-and-uneven-development-in-india
- https://shodhganga.inflibnet.ac.in/handle/10603/12260
- https://www.ijrti.org/papers/IJRTI2203016.pdf